स्वतंत्रता दिवस की 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर
प्रबंध संचालक,
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
का संदेश

प्रिय साथियों, बहनों और बच्चों,

1. स्वतंत्रता दिवस की 67 वीं वर्षगांठ पर आप सबको बधाई।

2. जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जिलों में अटल ज्योति अभियान के कार्यक्रम पूर्ण हो गए हैं। कंपनी में अटल ज्योति अभियान का प्रारंभ 2 अप्रैल 2013 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति मान्नीय डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और मान्नीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और अभियान का अंतिम कार्यक्रम कंपनी कार्य क्षेत्र में मुरैना जिले के अम्बाह तहसील में 27 जून 2013 को मान्नीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान कंपनी के सभी 16 जिलों में सभी के तत्पर एवं सामूहिक प्रयासों से अटल ज्योति अभियान के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अटल ज्योति अभियान गावों तक निरन्तर बिजली पहुॅचाकर विकास को नयी ऊर्जा देगा।

3. ''अटल ज्योति अभियान'' के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे घरेलु उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय करने हेतु प्रणाली उन्नयन के कार्य तेजी से किये जा रहे है। इस अभियान अंतर्गत 33 के.व्ही. लाईनों एवं 11 के.व्ही. लाईनों का निर्माण, नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवर लोड 11 के.व्ही. फीडरों का विभक्तिकरण एवं वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित है।

4. कंपनी द्वारा प्रणाली सुदृढीकरण योजना के तहत वर्ष 2013–14 में 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र व नये उपकेन्द्र 72 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मऱ 43 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि, 903.00 किमी. लम्बी 11 के.व्ही लाईन 1109 लम्बी 33 के.व्ही. लाइन, 192 नये वितरण ट्रासंसफार्मर एवं 648 वितरण ट्रासंसफार्मर की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निधारित किया गया है। जून 2013 तक 6 33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र, 14 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मऱ, 17 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्वि, 33 के.व्ही लाईन 187. 30 किमी., 219.81 किमी. 11 के.व्ही. लाइन, 13 वितरण ट्रासंसफार्मर एवं 23 वितरण ट्रासंसफार्मर की क्षमता वृद्धि लागत राशि रू. 35.43 करोड के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

5. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में ट्रांसफार्मरों की स्थापित संख्या 1,06,485 से बढ़कर 1,30,544 अर्थात् 24,059 वितरण ट्रांसफार्मर नये स्थापित किए गऐ एवं वितरण ट्रांसफार्मरों का फेल्युअर प्रतिशत 10.92 प्रतिशत से घटकर 9.80 प्रतिशत दर्ज हुआ। जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में घटकर 1.12 प्रतिशत कम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार पॉवर ट्रांसफार्मरों की स्थापित संख्या 1299 से बढकर 1515 अर्थात् 216 नये पॉवर ट्रांसफार्मर लगाये गये एवं फेल्युअर दर 3.31 प्रतिशत से घटकर 1.65 प्रतिशत अर्थात् 1.66 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

6. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 6 जनवरी 2013 से लाईनमेन एवं परीक्षण सहायकों के लिए 4 माह का वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम "पाठशाला" के कार्यक्रम के 48 आयोजन किए गए है। इस कार्यक्रम से जहां एक ओर लाईनमेन, ट्रांसफार्मर के रिनोवेशन के कार्य में प्रशिक्षित हुऐ वही साथ ही निम्न दाब वितरण प्रणाली का मेंटेनेंस भी किया गया। विद्युत आपूर्ति की चुनौती को लेकर परीक्षण सहायकों को भी पाठशाला कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।

7. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गुना, अशोकनगर, दतिया एवं श्योपुर जिलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं मुरैना, शिवपुरी, हरदा, बैतूल, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भिण्ड, राजगढ़ और ग्वालियर जिलें में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य प्रगति पर है। योजनांतर्गत 31 जुलाई 2013 तक 8539 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 7149 वितरण ट्रांसफार्मर लगाने एवं 3608 कि.मी. एल.टी. लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 1 लाख 71 हजार से अधिक बी.पी.एल. आवासों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके है।

8. कंपनी कार्य क्षेत्र में आर.ए.पी.डी.आर.पी.(पार्ट–बी) के अंतर्गत 31 शहरी क्षेत्रों में 833 करोड़ रूपये के विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं जिसके तहत 29 नये 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण, 13 अतिरिक्त पावर ट्रान्सफार्मर की स्थापना एवं 13 पावर ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि करना, नई 33 के.व्ही 199 कि.मी. एवं 11 के.व्ही. 741 कि. मी. लाइनों का निर्माण एवं कम क्षमता के कंडक्टर बदलना, 3320 नये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर की स्थापना करना के कार्य शामिल है। चोरी बहुल क्षेत्रों में एच.व्ही.डी.एस. कार्यो जिनमे 2972 नये एच.व्ही.डी.एस. ट्रान्सफार्मर की स्थापना तथा पुरानी एल.टी. लाइनों का कंडक्टर बदलकर 930 कि.मी ए.बी. केबिल डालने के कार्य तथा अन्य अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे है। योजना पूर्ण होने पर एटी. एण्ड.सी. लॉसेस को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अभी तक आर.ए.पी.डी.आर.पी.(भाग–बी) प्रोजेक्ट के तहत लगभग 202 फीडरों के कार्य पूर्ण कर लिये गए है। साथ ही 15 नवीन

33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों को ऊर्जीकृत किया गया है, 10 अतिरिक्त पावर ट्रान्सफार्मर की स्थापना एवं 13 पावर ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

9. स्थाई नवीन कृषि पंप अनुदान योजना के तहत वर्ष 2013–14 में 11 के.व्ही की 2082 किमी. 8000 नये वितरण ट्रासंसफार्मर, 288 किमी. निम्न दाब लाईन का विस्तार कर 10,000 पंपों के कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह जून 2013 तक 558 किमी. 11 के.व्ही, 2065 वितरण ट्रासंफार्मर, 122 किमी. निम्न दाब लाईन का विस्तार कर 2594 पंपों के कार्य पूण किये गये हैं।

10. कंपनी को वाणिज्यिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ने निम्नदाब उपभोक्ताओं के संयोजनों को उच्चदाब में परिवर्तित करने से राजस्व में वृद्धि तथा तकनीकी हानियों को कमी करने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13 में विगत वर्ष की तुलना में एटी.एंड.सी. हानियों में 8.72 प्रतिशत की कमी आई है। कंपनी ने वर्ष 2012–13 में अप्रैल 2012 से जून 2012 तक की अवधि में नगद राजस्व संग्रहण 923.47 करोड़ अर्जित किया था, जबकि इस वर्ष 2013–14 में इसी अवधि में 1046.93 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण किया गया है जो कि तुलनात्मक रूप से 13.37 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011–12 की अवधि में आर.पी.यू. 2.66 था जबकि वर्ष 2012–13 में आर.पी.यू. रू. 366 है। इस प्रकार आर.पी. यू. में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह जून 2013 तक नए 42 उच्चदाब कनेक्शन दिये गये हैं। माह जून 2013 तक कंपनी क्षेत्रांतर्गत कुल 1639 उच्चदाब कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके है।

11. समस्त विच्छेदित एवं संयोजित घरेलू एवं गैर घरेलू शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2013 से ''लोक मित्र योजना'' लागू की गई है। इस योजना में करीब 16000 उपभोक्ताओं ने ''लोक मित्र योजना'' का लाभ उठाया है एवं कंपनी द्वारा 2 करोड़ का अधिभार माफ किया गया है। इसी तरह ''दीन बंधु योजना'' लागू की गई जिसमें कंपनी एवं राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (अंत्योदय परिवारों सहित) उपभोक्ताओं के जून 2013 की स्थिति में संपूर्ण बिल की राशि माफ की जा रही है। ऐसे 4 लाख 77 हजार से अधिक बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ताओं की जून 2013 की स्थिति में राज्य शासन एवं कंपनी द्वारा 156 करोड़ रूपये की राशि माफ की गई है। यह वे बी.पी.एल. उपभोक्ता हैं, जो कि पहले से कंपनी की बिलिंग प्रणाली में सम्मिलित हैं। कंपनी द्वारा बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया राशि जो कि कंपनी की बिलिंग प्रणाली में सम्मिलित नहीं है, के लिए विशेष शिविरों के माध्यम से लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अब तक 174 शिविर आयोजित कर 24 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के बिल की राशि माफ

की गई है। कंपनी के कार्मिकों का आव्हान है कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की बकाया राशि माफ कर उनके घरों को रोशन करें।

12. मध्य क्षेत्र कंपनी उपभोक्ताओं के हित एवं सुविधाओं हेतु सतत् प्रयासरत रहा है। इसी दिशा में 1 जून, 2013 से समस्त निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन तथा एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर जाकर विद्युत बिल जमा करने को निःशुल्क कर दिया गया है। पूर्व में इन सेवाओं के लिये उपभोक्ताओं से रू. 5/– प्रति बिल शुल्क लिया जाता था।

13. उपभोक्ताओं को आसानी से बिल जमा करने के लिए भोपाल शहर एवं कंपनी कार्य क्षेत्र के विभिन्न शहरों में 40 ए.टी.पी. मशीनों की स्थापना की जा रही है। जुलाई 2013 में गोविंदपुरा स्थित ए.टी.पी. मशीन की सेवाएं उपभोक्ताओं को मिलना आरंभ हो गई है। चालू माह से भोपाल शहर के 09 स्थानों पर एटीपी मशीन की सुविधा आरंभ हो चुकी है।

14. उपभोक्ताओं के बिजली बिल संग्रहण हेतु मैसर्स इट्ज केशकार्ड लिमि. कंपनी की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु जुलाई, 2013 में अनुबंध किया गया है। मैसर्स इट्ज केशकार्ड लि. कंपनी द्वारा संपूर्ण कंपनी क्षेत्रांतर्गत शहरों में लगभग 550 से भी अधिक कियोस्क उपलब्ध कराये गये हैं, जो कि मुख्यतः शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में स्थित है, जहां पर उपभोक्ता बिजली के बिलों को निःशुल्क जमा कर सकते हैं। यह सेवा चालू माह अगस्त, 2013 के अंतिम सप्ताह से क्रियाशील हो रही है।

15. ऑनलाईन बिजली के बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशि की प्राप्ति का एस.एम.एस. द्वारा मोबाईल एवं ई–मेल पर संदेश देने की व्यवस्था जुलाई, 2013 से लागू हो गई है। अप्रैल, 2013 से बिजली बिल की सूचना एस.एम.एस. द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

16. कंपनी मुख्यालय में स्थापित डिस्काम कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा उचित भार नियंत्रण करते हुए वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान 1824 मिलियन यूनिट अधिक विद्युत प्रदाय किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 14.3% अधिक रहा । ''अटल ज्योति अभियान'' के तहत् गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घण्टे नियमित विद्युत प्रदाय किये जाने के कारण विद्युत भार में हुई वृद्धि को भी उचित भार प्रबन्धन के द्वारा नियंत्रित किया गया है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में कंपनी कार्य क्षेत्र में "SCADA" के तहत् सभी अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों पर डी.सी.यू. बाक्स की स्थापना कर दी गई है । इससे कुल 77 अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों एवं 30 नग अतिउच्चदाब

उपभोक्ताओं के फीडरों की वास्तविक समय में चालू एवं बन्द रहने की स्थिति, फीडर के भार, विद्युत खपत एवं विद्युत प्रदाय की अवधि की जानकारी उपलब्ध हो सकी है । इस तकनीक के द्वारा सभी वृत्तों एवं जिलों की प्रत्येक घण्टे की विद्युत मांग एवं आपूर्ति की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इस प्रणाली के माध्यम से 33 के.व्ही. फीडरों में व्यवधान की सूचना 15 मिनिट में वृत्त के महाप्रबंधक एवं क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को स्वतः एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाती है।

17. कंपनी की वेबसाइट www.dcclm.com के इनर्जी मैनेजमेन्ट सिस्टम पर सभी 11 के.व्ही. फीडरों का 24 घण्टे के भार का इन्द्राज कर वृत्त की अगले दिन की डिमांड फोरकार्स्टिग करने की सुविधा उपलब्ध है । इससे कंपनी की डिमाण्ड का सही आकलन कर कंपनी के इनर्जी चार्जेज को उचित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है । इनर्जी चार्जेज की मॉनिटरिंग एवं कंपनी के लिये उपलब्ध विद्युत का सही मांग पत्र भेजने में डिस्काम इनर्जी एकाउटिंग ग्रुप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । विद्युत मांग और आपूर्ति की सही प्लानिंग से कंपनी ऊर्जा व्यय में कमी लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत् है।

18. आर–एपीडीआरपी (पार्ट–ए) योजना के अंतर्गत तकनीकी एवं वितरण हानियों के पर्यवेक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली भी विकसित की जा रही है एवं साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की आवश्यक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। केन्द्रीयकृत कॉल सेन्अर (CCC) पर शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को स्वतः ही एस.एम.एस. के माध्यम से शिकायत क्रमांक की सूचना एवं शिकायत निवारण पर निवारण की सूचना दी जाती है। शिकायतों के समय पर निराकरण न होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी जा रही है। आर.ए.पी.डी.आर.पी (पार्ट–ए) के अंतर्गत 32 शहरी क्षेत्रों में तकनीकी एवं वाणिज्यक हानि की सही गणना एवं उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की सेवा देने के उद्देश्य से कंपनी की वर्तमान बिलिंग प्रणाली में परिवर्तन कर नई बिलिंग प्रणाली लागू की जा रही है! आर.ए.पी.डी. आर.पी (पार्ट–ए) में 21 मोडयूल है जिनमे महत्वपूर्ण बिलिंग से संबंधित मीटरिंग, बिलिंग, नवीन कनेक्शन, कलेक्शन एंव रिकनेक्शन/डिस्कनेक्शन मोड्यूल्स है। आर.ए. पी.डी.आर.पी के अंतर्गत 21 शहरो को केंन्द्रीय ग्राहक सेवा केन्द्र से जोडा जाना है, जिस के माध्यम से ग्राहको को बिजली संबंधी समस्यओं का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। बेव पोर्टल (webportal) पर ग्राहको के लिए बिल भुगतान के साथ साथ नवीन विद्युत संयोजन,विद्युत भार में परिवर्तन, पूर्व बिलों की जानकारी आदि सेवाऍ उपलब्ध है।

19. आपको बताना चाहेंगे कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012.13 के प्रावधिक वार्षिक लेखों को तैयार कर कंपनी कें संचालक मंड़ल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रावधिक वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2012–13 में कंपनी के राजस्व में 2011–12 की तुलना में 21% की वृद्धि तथा वर्ष बिजली क्रय मद में 22.50% की वृद्धि हुई है। कंपनी के द्वारा वर्ष 2012.13 में 1172 करोड़ रूपये के पूंजीगत कार्यों को कैपिटलाइज किया गया है। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी खर्चों को नियंत्रित करने हेतु बजट बनाया गया है। यह बजट वृत्तवार (Circlewise) एवं खर्चमदवार (Expenditure Headwise) बनाया गया है ताकि खर्चो को वृत्तवार नियत्रित किया जा सके एवं अनावश्यक खर्च को रोका जा सके। कंपनी द्वारा इस वर्ष ERP प्रणाली को पूर्णता प्रभावी करने हेतु कई कदम उठाये गये है जैसे कि अब ERP में CRA की Punching शुरू कर दी गई है, सभी प्राक्कलन भी ERP के माध्यम से ही बनाये जा रहे है एवं ऐसी आशा है कि इस वर्ष के अंत तक कंपनी में ERP प्राणाली पूरी तरह से लागू हो जायेगी।

20. कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के मासिक वेतन/पेंशन का भुगतान ई. आर.पी. प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2013 से सभी ठेकेदार एवं अन्य के भुगतान ई.आर.पी. प्रणाली के द्वारा ही किये जा रहें है। प्रशासनिक तंत्र की मजबूती एवं त्वरित कार्य हेतु ई.आर.पी. में स्वीकृति देने हेतु एस.एम.एस. के माध्यम से अलर्ट प्रेषित किये जा रहे हैं। 1 अगस्त 2013 से प्राक्कलनों (Estimate) की तकनीकी स्वीकृति ई.आर.पी. के माध्यम से देना प्रारंभ किया गया है।

21. चालू वर्ष 2013–14 में बढ़ी हुई विद्युत मांग की आपूर्ति करने हेतु 8 एम.व्ही.ए. क्षमता के 05 एवं 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के 111 नये पॉवर ट्रांसफार्मरों का प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त आगामी रबी सीजन में निम्न दाब भार प्रबंधन हेतु विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रांसफार्मर विद्युत प्रणाली में स्थापित करने के लिए भी इनकी पर्याप्त संख्या में आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। कंपनी एवं राज्य शासन के विभिन्न वित्तिय स्त्रोतों से पोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी प्रकार की सामग्री वर्तमान में क्षेत्रीय भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

22. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विद्युत वितरण की 7 सेवाएं आती हैं। इन 7 सेवाओं में 01 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013 तक 80 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि शतप्रतिशत समय–सीमा में निराकृत किए गए हैं।

23. कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग ने कंपनी कार्मिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कंपनी कैडर के नियमित कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा

की दृष्टि से धनवंतरी योजना लागू की गई है। इस योजना के लाभों से आप सभी परिचित होंगे। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से कंपनी में अंतिम रूप से स्थानांतरित एवं आमेलित कार्मिकों के लिए ''समूह बचत सह बीमा योजना'' भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कंपनी ने लागू की है। कंपनी ने 01 जनवरी 2013 से अपने कार्मिकों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन राहत में मॅहगाई भत्ते में वृद्धि की है। कंपनी ने मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, यात्रा के दौरा दैनिक भत्ता, होटल में ठहरने के किराए, स्थानांतरण भत्ता आदि में भी वृद्धि की है। अब कम्पनी में समाहित विद्युत सहकारी समितियों के नियमित सभी कार्मिकों को भी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने का विकल्प दिया गया है।

24. कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियोजित ढंग से भर्ती की प्रक्रिया की गई है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के लगभग 2000 से अधिक पदों पर पिछले 8 माह में भर्ती की गई है। जिन प्रमुख पदों पर भर्ती की गई है, उनमें परीक्षण सहायक, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट, मैनेजर (डी), मैनेजर (आई.टी.), जूनियर इंजीनियर (डी) तथा लाईन अटेण्डेन्ट (संविदा) के करीब 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

25. प्रशिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशील एवं जवाबदार बनाने के उद्देश्य से ''पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर'' भोपाल को पूर्ण–स्वयत्तता प्रदान करते हुए सोसायटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सोसायटी के कार्यो की लगातार समीक्षा के लिए सात–सदस्यीय कार्यकारणी कमेटी निर्मित की गई है। कमेटी न केवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर के कार्यो की समीक्षा करती है वरन् प्रशिक्षण हेतु नवाचार पर विचार करते हुए सुझाव भी देती है। वर्ष 2012–13 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर भोपाल द्वारा कुल 24740 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया है जो कि वर्ष 2011–12, में 15246 मानव दिवस प्रशिक्षण की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक है। प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने के लिए कंपनी क्षेत्र के प्रत्येक (संचा/संधा) एवं शहर संभागों में, दो–दिवसीय पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रत्येक कार्यक्रम में पी.डी.टी.सी. के प्रशिक्षको के मार्गदर्शन में एक 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन एवं एक 11/04 के.व्ही. वितरण ट्रांसफारमर का पूर्ण रूपेण रख–रखाव कर प्रयोगिक प्रशिक्षण संभाग के तकनीकी कर्मचारियो को दिया गया। कर्मचारियो को रख–रखाव से सम्बन्धित साहित्य भी वितरित किया गया।

26. विभाग के कार्यालय सहायको के लिए प्रशिक्षण शैली मे परिवर्तन कर 15 दिवसीय इन्टप्राईज रिसोर्स प्लानिंग–माड्ल (ई.आर.पी.) आधारित प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2012–13 में कुल 304 कार्यालय सहायको को ई.आर.पी. का प्रशिक्षण दिया गया है। विभागीय अधिकारियों को भी ई.आर.पी. प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

27. आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अन्तर्गत भोपाल एवं ग्वालियर शहरो में SCADA (सुपरबायजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्वि जिशन) प्रणाली के कार्य किये जा रहे है। भोपाल एवं ग्वालियर शहर में पदस्थ अधिकारियो एवं कर्मचारियो को SCADA प्रणाली में कार्य करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

28. अधिकारियों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि एवं नवीन तकनीकी के उपयोग हेतु पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर द्वारा सेन्टर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.पी.आर.आई) बैगलोर के साथ करार किया गया है। इस करार से कंपनी के कर्मचारियो/ अधिकारियो को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण सुलभ होगा, वरन् कंपनी के पी.डी.टी.सी. को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विकसित करने में इससे मदद मिलेगी।

29. अन्त में, मैं यहां सभी पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूॅ तथा सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूॅ कि हम सब बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर कार्य निष्पादन एवं उच्च कोटि की उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, राज्य शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

30. कंपनी क्षेत्र के समस्त जिलों में ''अटल ज्योति अभियान'' के अंतर्गत 24 घंटे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था चालू हो गई है। कंपनी के लिए यह चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक समय है एवं मध्यप्रदेश के लिए नये युग की शुरूआत है। आगामी समय में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए आपके सम्मिलित एवं सार्थक प्रयासों की कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

(नीतेश व्यास)
प्रबंध संचालक